नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

1. कोयला क्षेत्र में उत्पादन और दक्षता बढ़ाने से संबंधित उपायः वर्धित अन्वेषण प्रयास

सीएमपीडीआई गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई विभागीय संसाधनों, एमईसीएल और निविदा के माध्यम से कार्य निष्पादित करता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान गैर–सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में वास्तविक ड्रिलिंग लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(लाख मीटर में ड्रिलिंग)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि%
2019-20	7.60	7.88	29%
2020-21	7.65	7.70	-2%
2021-22	3.40	4.28	-44%
2022-23	2.00	2.58	-40%
2023-24	3.50	4.29	66%

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान सीआईएल ब्लाकों में वास्तविक ड्रिलिंग की तुलना में लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

(लाख मीटर में ड्रिलिंग)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में वृद्धि%
2019-20	6.30	5.80	-30
2020-21	4.95	5.45	-6
2021-22	4.35	3.98	-27
2022-23	4.19	3.58	-10
2023-24	3.70	3.80	6

उपरोक्त के अलावा, सीएमपीडीआई ने एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से कोयला और गैर–कोयला में भी अन्वेषण किया है और वित्त वर्ष 2023–24 में 0.34 लाख मीटर ड्रिलिंग पूरी कर ली है। 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, एनएमईटी फंडिंग के माध्यम से 0.45 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई है।

2. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनीकृत नीति पर जोर

उत्पादन स्तर के उच्च ट्रेजेक्ट्री को 773 मिलियन टन (मि.ट.) के अपने पिछले स्तरों को बनाए रखने और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ कोयले के गैर–आवश्यक आयात को समाप्त करने के लिए, सीआईएल ने समयबद्ध तरीके से 1 बिलियन टन (बि.ट.) कोयला उत्पादन करने की योजना बनाई है। सीआईएल ने प्रमुख संसाधनों की पहचान की है और अनुमानित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनके संबंधित मुद्दों का आकलन किया है। हालांकि, भविष्य में लक्ष्यों को पूरा करना वास्तविक मांग परिदृश्य पर निर्भर करेगा जो विकास के भविष्य के पाठ्यक्रम की शर्तों को निर्धारित कर सकता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएएल) ने कोयला उत्पादन में 770 मिलियन टन (मि.ट.) का आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है। 2023–24 में, वार्षिक कोयला उत्पादन लक्ष्य 780 मि.ट. आंका गया था और सीआईएएल ने 774 मि.ट. का कोयला उत्पादन हासिल किया था। 2024–25 के लिए सीआईएल का वार्षिक लक्ष्य 838 मि.ट. है। 2023–24 की अवधि के दौरान समूह–वार उत्पादन योजना और वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है।

(आंकड़े मि.ट. में)

सीआईएल	2023-24		2024-25
	एपी लक्ष्य	वास्तविक	एपी लक्ष्य
मौजूदा और पूर्ण	204.4	204.4	838
जारी परियोजनाएं	575.4	568.8	
भावी परियोजनाएं	0.2	0.3	
कुल	**780.0**	**773.4**	

सीसीएल में उत्तरी करनपुरा कोलफील्ड, एसईसीएल के कोरबा कोलफील्ड और एमसीएल में ईब तथा तालचेर कोलफील्ड से उत्पादन में एक बड़ी वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

3. परियोजनाओं को पूरा करना और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वित्त–वर्ष 2023–24 के दौरान, सीआईएल में 16 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 03 खनन परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

31.03.2024 तक, 895.93 एमटीवाई की कुल स्वीकृत क्षमता और 133567 करोड़ रुपए की कुल स्वीकृत पूंजी के साथ 119 जारी कोयला परियोजनाएं (20 करोड़ रुपए और अधिक की लागत) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन और पूरा होना महत्वपूर्ण बाहरी कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि भूमि का कब्जा, हरित मंजूरी, निकासी बुनियादी ढांचा आदि।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सीआईएल द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

क) झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भूमि के कब्जे में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार अनुनय–विनय। इसके अलावा, भूमि मालिकों को लगातार मुआवजा स्वीकार करने और कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि को सौंपने के लिए राजी किया जा रहा है।

ख) एफसी के अनुदान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार के साथ निरंतर समन्वय और संपर्क।

ग) लगातार कानून और व्यवस्था के मुद्दों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने हेतु सभी स्तरों पर कोयला कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को लगातार राजी किया गया है।

घ) सहायक कंपनी और सीआईएल स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कोयला मंत्रालय 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की मासिक आधार पर समीक्षा करता है।

ड.) परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है। कोयला मंत्रालय विशेष रूप से वानिकी मंजूरी और भूमि के भौतिक कब्जे की सुविधा के लिए अपनी ओर से अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन

को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

प्रभावी निगरानी और त्वरित तथा सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, सीआईएल द्वारा ईआरपी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जो परियोजनाओं/ खानों के हर विवरण को सम्मिलित करता है, प्रदर्शन का विश्लेषण करता है और प्रासंगिक रिपोर्ट तैयार करता है।

परियोजनाओं की मानीटरिंग ईआरपी पोर्टल के पीएस मॉडयूल के माध्यम से की जाती है।

कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सीआईएल ने पहले ही नई परियोजनाएं और ओसी पैच शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा, मौजूदा खानों/परियोजनाओं का क्षमता विस्तार ईसी विस्तार के माध्यम से या जहां भी संभव हो, ईपीआर के माध्यम से किया जा रहा है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

31.03.2024 तक, एससीसीएल की 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली 11 परियोजनाएं हैं, जिनकी निगरानी ओसीएमएस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इन्हें मासिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है।

4. कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

4.1 कोयले के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं –

i. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii. कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित पद्धति से खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय करने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 का अधिनियमन।

iii. कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल।

iv. कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरियां प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v. राजस्व शेयरिंग आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के तहत, उत्पादन की निर्धारित तारीख से पहले उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ. साथ, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) दिया गया है।

vi. वाणिज्यिक कोयला खनन के नियम और शर्तें बहुत उदार हैं, जिसमें कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नई कंपनियों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है, अग्रिम राशि में कमी की गई है, मासिक भुगतान के लिए अग्रिम राशि का समायोजन, कोयला खानों के प्रचालन के लिए लचीलेपन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मानदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल शामिल है।

4.2 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सभी आवश्यक संसाधनों जैसे पर्यावरण मंजूरी/वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी)/ साइलो के जरिए मशीनीकृत लोडिंग जैसी निकासी अवसंरचनाओं, रेल परियोजनाओं आदि को पूरा करने हेतु पहचान कर ली है और कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआईएल खानों (ब्राउनफील्ड परियोजनाओं) के विस्तार, नई खानों (ग्रीनफील्ड परियोजनाओं) को खोलने, भूमिगत (यूजी) और ओपनकास्ट (ओसी) दोनों की अपनी खानों के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से अपने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अपनी यूजी खानों में, सीआईएल जहां भी संभव हो, मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) के साथ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज (एमपीटी) को

अपना रही है। सीआईएल ने हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। अपनी ओसी खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर और सरफेस माइनर्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

4.3 कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए एससीसीएल द्वारा किए जा रहे उपाय:

वर्तमान में, एससीसीएल तेलंगाना राज्य में 39 खानों (22–भूमिगत और 17–ओपनकास्ट) का संचालन कर रही है। ओडिशा राज्य में एससीसीएल को आवंटित नैनी कोयला खान के वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू होने की उम्मीद है। एससीसीएल ने 2024–25 के अंत तक उत्पादन को 77 मिलियन टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की है। उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- 7 नई खानें खोलने की योजना (जीवीसीएफ में 6 और तालचेर में 1)।
- कोयला निकासी अवसंरचना सुविधा में सुधार: एससीसीएल अपने सीएचपी को संशोधित कर रहा है, नए सीएचपी, क्रशर का निर्माण कर रहा है।
- कोयले की निकासी के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण और नई रेलवे लाइनें बिछाना।
- कोयले के प्रेषण स्थल तक कम दूरी के परिवहन के लिए सड़कों का विकास।

4.4 कोयले का उत्पादन बढाने के लिए एनएलसीआईएल द्वारा किए गए उपाय

एनएलसी इंडिया ने वर्ष 2023–24 के दौरान, तालाबीरा II और III कोयला खानों से 12 मि.ट. के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। कोयले की उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए, एनएलसी इंडिया लिमिटेड तालाबीरा खान के कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वर्ष 2023–24 के दौरान, तालाबीरा कोयला उत्पादन 12.68 मि.ट. तक पहुंच गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024–25 के लिए तालीबारा ᑭ और ᑭᑭ ओसीपी का कोयला उत्पादन 16.1 मि.ट. तक बढ़ा है। इसके अलावा, पचवाड़ा साउथ कोयला ब्लॉक जो एनयूपीपीएल (एनएलसीआईएल की सहायक कंपनी) को आवंटित किया गया है, उन्नत खान विकास चरण में है। चरण–I एफसी स्वीकृति लंबित है। इस खदान के दिसंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 1.68 मि.ट. है। सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर, एनएलसीआईएल वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लगभग 17.78 मि.ट. का उत्पादन कर सकता है। उपर्युक्त प्रयासों से न केवल अन्त्य उपयोग संयंत्रों को ईंधन सुरक्षा मिलेगी बल्कि बाजार में कोयला भी उपलब्ध होगा।

5. सीआईएल में प्रौद्योगिकी विकास और खानों का आधुनिकीकरण

भूमिगत खानों का मशीनीकरण:

राष्ट्र का विजन 2047, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, ने भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला है। अभ्यास से जो विकसित हुआ वह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोयला राष्ट्र की ऊर्जा आपूर्ति मिश्रण में प्रमुख बना हुआ है। इसके अलावा, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त की जानी चाहिए जिसमें पर्यावरण के अनुकूल खनन के तरीके शामिल हैं जिससे भूमिगत खानों के महत्व और प्रासंगिकता में काफी वृद्धि हुई है। इसलिए, सीआईएल एक यूजी विजन योजना तैयार कर रही है जो अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसके अनुसार, सीआईएल ने वर्ष 2029–30 के अंत तक 100 मिलियन टन उत्पादन की परिकल्पना की है। बड़े पैमाने पर कंटीन्यूअस माइनर (सीएम) शुरू करने के साथ–साथ बड़ी संख्या में हाईवॉल खानों को लागू करके यूजी बंद/चालू ओसी खानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूजी उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। यूजी उत्पादन बढ़ाने का एक और तरीका राजस्व साझाकरण मॉडल द्वारा एमडीओ के माध्यम से परित्यक्त/बंद खानों को फिर से खोलकर लिया गया है। वर्तमान में, लगभग 14.88 एमटीवाई की कुल क्षमता के साथ सीआईएल की 20 यूजी खानों में 30 कंटीन्यूअस माइनर्स (सीएम) तैनात किए गए हैं।

उक्त यूजी विजन प्लान के अनुसार, सीआईएल ने 2029–30 तक लगभग 45.12 एमटीवाई की क्षमता के साथ 110 अन्य सीएम को चालू करने की योजना की परिकल्पना की है।

वर्तमान में, 2.36 मि.ट. की क्षमता वाले 5 हाईवॉल खनिक कार्य कर रहे हैं और अतिरिक्त 25 हाईवॉल खनिक वर्ष 2029–30 में शुरु किए जाएंगे। एमडीओ के माध्यम से राजस्व साझाकरण मॉडल पर परित्यक्त/बंद खानों की नीलामी के उद्देश्य से अब तक कुल 36 खानों (दौर–I में 20 खान, दौर–II में 7 खान, दौर–III में 7 तथा दौर–IV में 2 खान) की पहचान की गई है। इसमें से 31.295 एमटीवाई की प्रस्तावित क्षमता वाली 20 खानों के लिए एलओए जारी कर दिए गए हैं और शेष खानें प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, खान श्रमिकों के अनुत्पादक यात्रा समय को कम करने के उद्देश्य से कई भूमिगत खानों में मैन–राइडिंग प्रणाली शुरू की गई है। वर्तमान में, सीआईएल की खानों में 55 मैन–राइडिंग सिस्टम प्रचालन में हैं। सीआईएल की भूमिगत खानों के लिए 13 अन्य मैन राइडिंग योजनाएं तैयार की गई हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक के साथ प्रस्तावित कुछ भूमिगत खानों के लिए, पुरुषों और सामग्री के लिए ट्रैकलेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रस्तावित किया गया है। तदनुसार, ईसीएल की झंझरा और कोट्टाडीह भूमिगत खान में वर्तमान में पांच फ्री–स्टीयर वाहन और छह बहु–उपयोगी वाहन चल रहे हैं।

ओपन कास्ट खानों का मशीनीकरण:

- सीआईएल ने कार्य क्षमता में सुधार के लिए अत्याधुनिक तकनीक शुरु की है। गेवरा एक्सपेंशन, दीपका और कुसमुंडा ओपन कास्ट खानों में 240 टि रियर डम्पर के साथ 42 सह–शॉवेल जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम शुरु किए गए हैं जबकि, एनसीएल की अम्लोहरी, दुधीचुआ, जंयत, खडिया और निगाही तथा ईसीएल के राजमहल में 190 टी रियर डम्पर के साथ 20 सह–शॉवेल चल रहे है।
- परिचालन दक्षता, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ओपनकास्ट खानों में सर्फेस माइनर्स को बड़े पैमाने पर शुरु किया गया है। 2020–21 के दौरान सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन का 50.16% सर्फेस माइनर्स का उपयोग करके प्राप्त किया गया था और यह 2022–23 के दौरान बढ़कर 53.75% हो गया है। वित्त वर्ष 2023–24 में, सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन में भूतल खनिक का योगदान 54.91% है। 1.4.2024 तक, सीआईएल की कई ओपनकास्ट खानों में हायरिंग मोड के माध्यम से तैनात भूतल खनिकों के अलावा विभागीय भूतल खनिकों की संख्या 47 है।
- वाहनों की आवाजाही की वास्तविक समय निगरानी को सक्षम करने के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग, बूम बैरियर के साथ आरएफआईडी प्रणाली आधारित निगरानी उपकरण आरंभ किए गए हैं जो चोरी आदि के खिलाफ सुधारात्मक उपायों की सुविधा प्रदान करते हैं।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से खान की समग्र दक्षता और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, सीआईएल ने सात (07) चयनित ओपनकास्ट खानों (एसईसीएल के 3 और एनसीएल के 4) में 'डिजिटल परिवर्तन' के लिए पहल की है।
- खान योजना के लिए भूवैज्ञानिक और खान मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अनुकूल नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा रहा है। यह पिट डिजाइन, पिट ऑप्टिमाइजेनशन, संसाधनों और डंप की शेड्यूलिंग आदि के माध्यम से सर्वोत्तम संसाधन योजना प्रदान करता है। चट्टान और मिट्टी की ढलानों की स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए भू–तकनीकी सॉफ्टवेयर/उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है।
- डब्ल्यूसीएल की एक खान, एसईसीएल की 03 खानों और ईसीएल की एक खान में स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया गया है। एसएंडटी स्टडी के तहत एनसीएल के दुधिचुआ ओसी में एक और स्लोप स्टेबिलिटी रडार तैनात किया गया है। भविष्य में सीआईएल की अन्य बड़ी खानों में स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया जाएगा।
- एमसीएल की दो खानों में और एसईसीएल की एक खान में ओवरबर्डन के निष्कर्षण के लिए विब्रो रिपर्स लगाए गए हैं। साथ ही, ओबी के निष्कर्षण के लिए सरफेस माइनर लगाने के लिए ओईएम के साथ परामर्श किया जा रहा है।

- सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में ड्रोन–आधारित भूतल सर्वेक्षण किया जा रहा है।
- इसके अलावा, सीआईएल अपने मानव, भौतिक और वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और अन्य आईटी–सक्षम प्रणाली शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो सीआईएल की परिचालन दक्षता को एक बड़ा बढ़ावा देगा।

सर्वेक्षण और अन्वेषण

- उच्चतम स्तर की सटीकता के लिए, सर्वेक्षण और माप कार्य के लिए कुल स्टेशन और 3डी टीएलएस सर्वेक्षण उपकरण पहले ही पेश किए जा चुके हैं। सीएमपीडीआईएल द्वारा ऑप्टिकल सेंसर, एलआईडीएआर और थर्मल सेंसर से लैस हाई एंड सर्वे ग्रेड ड्रोन टेक्नोलॉजी की खरीद की गई है, जिसका उपयोग विभिन्न सर्वेक्षण उददेश्यों जैसे वॉल्यूमेट्रिक मापन, स्थालिकृतिक सर्वेक्षण, माइन फायर जोन की थर्मल मैपिंग, चेंज डिटेक्शन, मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन और खान प्रचालन के लिए डिजिटल टेरेन मॉडल तैयार करने के लिए किया जाएगा।
- ज्योमिटिक्स प्रभाग, सीएमपीडीआई में गति शक्ति प्रकोष्ठ का निर्माण
- सीआईएल कार्य आदेश के अनुसार पीएमजीएस–पोर्टल पर कोयला ब्लॉक, खनन संबंधी सूचना, कोयला निकासी, भूमि डेटा और अन्य विषयगत लेयर्स का अद्यतनीकरण। डेटा अपलोडिंग और अपडेशन नियमित आधार पर किया जाता है।
- अन्वेषण कार्य में, अत्यधिक लहरदार स्थलाकृति और कम पहुंच क्षमता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्रों आदि के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी की शुरूआत के माध्यम से प्रगति हासिल की जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके कम समय में अधिक आधार कवर किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर में हाल के विकास के कारण, इस हाई डेफिनिशन डाटासेट को संभालना काफी आसान हो गया है और पूरे क्षेत्र के लिए अयस्क/खनिज निकायों, बेसमेंट आदि की सटीक मॉडलिंग की जा सकती है। इसके अलावा, भूकंपीय सर्वेक्षण प्रक्रिया, सामान्य सतही इलाके में एक पारंपरिक अन्वेषण तकनीक (2डी/3डी) का उपयोग विभागीय के साथ–साथ कोयला अन्वेषण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। भूकंपीय डेटा प्रोसेसिंग और व्याख्या अत्याधुनिक आयातित सॉफ्टवेयर, पैराडिम के माध्यम से की जा रही है। इस सॉफ्टवेयर के अलावा, आत्मनिर्भर भारत पहल के एक हिस्से के रूप में, भूकंपीय आउटपुट और रिज़ॉल्यूशन में सुधार के लिए सीएमपीडीआई और गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जीईआरएमआई) गांधीनगर द्वारा संयुक्त रूप से स्पेक्ट्रल एन्हांसमेंट (एसपीई) नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। भूभौतिकीय लॉग डेटा की ऑटोमैटिक इंटरप्रिटेशन के लिए इन–हाउस विकसित एआई/एमएल मॉड्यूल परिणामों की सटीकता को बढ़ाता है और इंटरप्रिटेशन समय को भी कम करता है।

एनएलसी खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण:

एनएलसी इंडिया लिमिटेड भारत में लिग्नाइट और कोयला खनन में अग्रणी है, जिसने खानों और थर्मल इकाइयों के अपने विभिन्न क्षेत्रों में नई खनन तकनीकों को अपनाया है।

खनन क्षेत्र में अपनाई जा रही नवीनतम तकनीकों का सारांश नीचे दिया गया है:

एनएलसीआईएल के नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवाचार:

1. **ओबी/लिग्नाइट/कोयला का स्थानिक डाटा विजुअलाइज़ेशन और वॉल्यूम मापन**
   - एनएलसीआईएल भारत में अपने सभी लिग्नाइट और कोयला खानों में डीटीएम से डीटीएम पर आधारित आईबी, ओबी, कोयला और लिग्नाइट के आयतन मापन के लिए 3डी टीएलएस का उपयोग कर रहा है।

2. ट्रिम्बल आर 12 डीजीपीएस और 3डी–टीएलएस के एकीकरण के साथ भू–स्थानिक डेटा जनरेशन जो खानों में टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर के उपयोग में एक बेंचमार्क अनुकूलन करेगा।

3. **भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस):**

- ये भू–स्थानिक डाटा किसी वस्तु के स्थान, आकार और आकार प्रस्तुत करते हैं।
- जीआईएस का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है
  - ओबी/आईबी/लिग्नाइट/कोयला आरक्षित अनुमान।
  - भू–रासायनिक और जल विज्ञान डेटा।
  - रिपोर्ट जनरेशन।

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/रद्द आवंटन वाली कोयला खानों का आवंटन

रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों में से, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अब तक कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 121 कोयला खानें आवंटित की हैं, जिनमें से 57 कोयला खानें प्रचालनरत हो गई हैं जबकि 54 कोयला ब्लॉक उत्पादन के अधीन हैं।

2023–24 के दौरान, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द/डी–आवंटित की गई कोयला खानों में से सीआईएल/उसकी सहायक कंपनियों को 16 कोयला ब्लॉकों को आवंटित किया गया है।

7. एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों का आवंटन

एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अब तक 40 कोयला खानें आबंटित की गई हैं। 2023–24 के दौरान, एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के तहत 16 कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आवंटन के लिए नीतिगत सुधार:

कोयले की बिक्री के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन भारत में पहली बार 18 जून 2020 को घरेलू कोयले के उत्पादन को बढ़ाने और कोयला क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। 4 वर्षों की छोटी अवधि के भीतर, 225 मि.ट. की पीक रेटेड क्षमता वाली 104 कोयला खानों की नीलामी के 9 दौर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। वाणिज्यिक कोयला खनन से कोयला क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

8. गुणवत्ता और तृतीय पक्ष द्वारा नमूनाकरण– हाल के निर्णय

कोयले की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत यूटिलिटिज) की चिंताओं को दूर करने के लिए, थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2015 में पेश की गई थी। लोडिंग एंड पर थर्ड पार्टी सैंपलिंग के संबंधी दिशा–निर्देश– मानक संचालन प्रक्रिया 26.11.2015 को जारी की गई थी। नीति के अनुसार, विद्युत संयंत्र (उपभोक्ता) और कोयला कंपनियों (आपूर्तिकर्ता) दोनों की ओर से लदान स्तर पर कोयले के नमूने और विश्लेषण का कार्य करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सीआईएमएफआर द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी नियुक्त की जानी थी। सीआईएमएफआर को ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा अनलोडिंग/प्राप्ति एंड पर कोयले के नमूने लेने और विश्लेषण करने की भी अनुमति दी गई थी। संयुक्त सचिव (कोयला) और संयुक्त सचिव (थर्मल) द्वारा संयुक्त रूप से थर्ड पार्टी सैंपलिंग की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

थर्ड पार्टी सैंपलिंग का विस्तार विभिन्न एफएसए और वैकल्पिक आधार पर ई–नीलामी के अंतर्गत कोयला लेने वाले गैर–विद्युत उपभोक्ताओं तक भी किया गया है।

सीआईएमएफआर ने 11.11.2023 से थर्ड पार्टी सैंपलिंग गतिविधियों को बंद कर दिया है।

विद्युत मंत्रालय की ओर से पीएफसी ने थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों का पैनल बनाने के लिए निविदा के दो दौर आयोजित किए हैं और पहले दौर के दौरान 01 थर्ड पार्टी

सैंपलिंग एजेंसी और दूसरे दौर के दौरान 10 थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसी को पीएफसीएल द्वारा पैनल में शामिल किया गया है।

उपभोक्ता किसी भी पैनलबद्ध थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों की सेवाएं लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।

इसके अलावा, क्यूसीआई (सरकारी स्वायत्त निकाय) और सीआईएमएफआर (एक सरकारी उद्यम) को भी पीएफसीएल निविदा की सबसे कम डिस्कवर्ड मूल्य पर इस कार्य की पेशकश की गई थी। जबकि क्यूसीआई ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, सीआईएमएफआर ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

वर्तमान में, 12 थर्ड–पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों को थर्ड–पार्टी सैंपलिंग का काम करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है

9. कोयला लिंकेज का युक्तिकरण:

कोयला लिंकेज का युक्तिकरण कोयला मंत्रालय की एक नीतिगत पहल है ताकि कोयला खानों से उपभोक्ता तक कोयले की ढुलाई में दूरी को कम किया जा सके। विद्युत क्षेत्र में कोयला लिंकेज युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खानों से विद्युत संयंत्रों तक परिवहन लागत में कमी आई है जिससे अधिक दक्ष कोयला आधारित विद्युत उत्पादन हुआ है। यह उपयोग परिवहन अवसंरचना पर भार को कम करने, निकासी बाधाओं को कम करने के साथ–साथ कोयले की उतराई लागत में कमी लाने में मदद करता है। आईपीपी/निजी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए कोयले के युक्तिकरण की पद्धति भी 15.05.2018 को जारी की गई थी। पिछले यौक्तिकीकरण उपयोगों को केवल विद्युत क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। लिंकेज युक्तिकरण पर 2020 में तैयार की गई नई पद्धति में विद्युत के साथ–साथ गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) को भी शामिल किया गया है और आयातित कोयले के साथ कोयले की अदला–बदली की भी अनुमति दी गई है।

अब तक, कुल 92.16 मिलियन टन कोयले को युक्तिसंगत बनाया गया है और इससे अब तक 6420.00 करोड़ रुपये की वार्षिक संभावित बचत हुई है। दिसंबर, 2023 के दौरान, प्रति वर्ष लगभग 580 करोड़ की संभावित बचत के साथ 6.72 मिलियन टन की लिंकेज मात्रा के लिए युक्तिकरण का तीसरा दौर संपन्न हुआ।

10. गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी

गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी के लिए नीति वर्ष 2016 में पेश की गई थी। नीति में निर्धारित है कि एनआरएस (उर्वरक (यूरिया) को छोड़कर) के लिए कोयला लिंकेज का आबंटन नीलामी आधारित होगा। केवल सीपीएसई और उर्वरक (यूरिया) के लिए पूर्ववर्ती ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) का नवीकरण किया जाएगा। नीति के तहत एफएसए अधिकतम 15 वर्षों की अवधि के लिए होगा। 2020 में शुरू की गई नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 साल तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। एनआरएस के विभिन्न उप–क्षेत्रों के लिए अलग–अलग मात्रा निर्धारित की जाती है और नीलामी उप–क्षेत्रों के लिए आयोजित की जाती है।

वर्तमान में, एनआरएस लिंकेज नीलामी का 7वां दौर चल रहा है। एनआरएस लिंकेज नीलामियों के अंतर्गत सफल बोलीदाताओं द्वारा अब तक 170.50 मिट कोयले की मात्रा बुक की गई है

कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत 2022 में एक नया उप–क्षेत्र *'सिन–गैस का उत्पादन करके कोयला गैसीकरण की ओर अग्रसर होना'* बनाया गया है ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम किया जा सकेगा। एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत एक और नया उप–क्षेत्र "डब्ल्यूडीओ मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करके इस्पात" के नाम के साथ मार्च 2024 में बनाया गया है। आशा है कि नए उप–क्षेत्र से देश में इस्पात उद्योग में घरेलू कोकिंग कोयले की खपत में वृद्धि होगी।

11. सरकार ने मौजूदा लेटर ऑफ एंश्योरेंस (एलओए) – ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) प्रणाली को खत्म करने की मंजूरी दी और भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) के दोहन और आवंटन के लिए योजना (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा 22.05.2017 को

जारी किया गया था। उक्त नीति में संशोधन वर्ष 2019 और 2023 में भी पेश किए गए हैं। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके विभिन्न पैराओं के तहत उल्लिखित है) इस प्रकार हैं:

पैरा क: एफएसए पर लंबित एलओए धारकों के साथ यह सुनिश्चित करने के बाद हस्ताक्षर किए जा सकते हैं कि संयंत्र चालू हो गए हैं, संबंधित उपलब्धि प्राप्त हुई है, एलओए की सभी निर्दिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा किया गया है और जहां एलओए धारक के खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया जाता है। इसके अलावा, इसने मौजूदा कोयले की आपूर्ति को वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के 75% की दर से लगभग 68,000 मेगावाट की क्षमता तक जारी रखने की अनुमति दी है, जिसे भविष्य में कोयले की उपलब्धता के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। नीति ने एफएसए के मुकाबले लगभग 19,000 मेगावाट क्षमता के लिए एसीक्यू के 75% पर कोयले की आपूर्ति को सक्षम किया है, जिसे चालू करने में देरी हुई है, बशर्ते ये संयंत्र 31.03.2022 के भीतर चालू हो जाएं। डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित बोलियों के लिए भविष्य में संपन्न होने वाले मध्यम अवधि के विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) को भी लिंकेज कोयला आपूर्ति के लिए योग्य बनाया गया है।

पैरा ख (i): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केंद्रीय जेनको/संयुक्त उद्यमों को कोयला लिंकेज प्रदान कर सकती है।

पैरा ख (ii): घरेलू कोयले पर आधारित दीर्घकालिक पीपीए वाले स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) से लिंकेज, जहां नीलामी में भाग लेने वाले आईपीपी टैरिफ पर छूट के लिए बोली लगाएंगे (पैसे/यूनिट में)। जो बोलीदाता किसी भी कारण से ख (**ii**) के तहत लिंकेज नीलामी में भाग नहीं ले सके, उन्हें इस नीति की ख(**ii**) नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, जो बोलीदाता पूर्ण एसीक्यू के लिए लिंकेज सुरक्षित नहीं कर सके, वे बेंचमार्किंग छूट के बाद ख(ii) के तहत बाद के चरण में भविष्य की नीलामी में भाग लेकर शेष राशि के लिए लिंकेज प्राप्त कर सकते हैं।

पैरा ख (iii): पीपीए के बिना आईपीपी/विद्युत उत्पादकों से लिंकेज नीलामी के आधार पर होगा।

पैरा ख (iv): राज्यों को विवरण के साथ कोल लिंकेज की उपलब्धता की पूर्व–घोषणा करके नए पीपीए के लिए कोल लिंकेज भी निर्धारित किए जा सकते हैं। राज्य इन लिंकेज को डिस्कॉम्स/राज्य द्वारा नामित एजेंसियों (एसडीए) को इंगित कर सकते हैं।

पैरा ख (v): राज्यों के समूह की विद्युत की आवश्यकता को भी एकत्र किया जा सकता है और इस तरह की एकत्रित विद्युत की खरीद एक एजेंसी द्वारा की जा सकती है, जिसे विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है या ऐसे राज्यों द्वारा टैरिफ आधारित बोली के आधार पर अधिकृत किया गया है।

पैरा ख (vi): केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) स्थापित करने के लिए नामित एजेंसी द्वारा निगमित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों के तहत विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पूर्ण मानक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा।

पैरा ख (vii): कोयला मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय के परामर्श से, उपभोक्ताओं को लागत बचत के पूर्ण पास के साथ आयातित कोयले के आधार पर, पीपीए वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया की विस्तृत पद्धति तैयार कर सकता है।

पैरा ख (viii):

(क) बिना पीपीए वाले विद्युत संयंत्रों को डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डीईईपी) पोर्टल के किसी भी उत्पाद के माध्यम से पावर एक्सचेंज के माध्यम से या अल्पावधि में डे अहेड मार्केट (डीएएम) में लिंकेज के माध्यम से उत्पन्न विद्युत की बिक्री के लिए ख(पपप) और ख(पअ) के तहत न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए अधिकतम 1 वर्ष तक कोयला लिंकेज की अनुमति है।

(ख) डीईईपी पोर्टल या जनरेटर द्वारा पावर एक्सचेंज का उपयोग करके शॉर्ट टर्म पीपीए के माध्यम से विद्युत की बिक्री के लिए मौजूदा कोयला लिंकेज का उपयोग, जो

डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के मामले में पीपीए को समाप्त करता है, अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए या जब तक वे लंबी/मध्यम अवधि के पीपीए के तहत विद्युत का दूसरा खरीदार खोजें, जो भी पहले हो।

(ग) ख(v) के तहत कोयला लिंकेज उन मामलों में भी लागू होता है, जहां विद्युत मंत्रालय द्वारा नामित नोडल एजेंसी ऐसे राज्यों से मांग के बिना भी राज्यों के समूह के लिए विद्युत की आवश्यकता को एकत्रित/खरीदती है।

(घ) केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियां संकटग्रस्त विद्युत संपत्तियों की शक्ति के एक समूह के रूप में कार्य कर सकती हैं।

ड.) ऋण का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु तंत्र।

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के तहत निम्नलिखित क्षमताओं को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है (01.01.23 की स्थिति के अनुसार):

(i) शक्ति नीति के पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 8,780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 एलओए धारकों को ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है।

(ii) शक्ति नीति के पैरा ख (i) के प्रावधानों के तहत 51 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को कुल 58,680 मेगावाट क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

(iii) शक्ति ख (ii) के तहत, नीलामी के कुल छह दौर पूरे हो चुके हैं, जिसमें कुल बुक की गई मात्रा 38.85 मि.ट. है।

(iv) शक्ति ख(iii) के तहत, अब तक नीलामी के पांच दौरों में कुल 28.94 मि.ट. मात्रा बुक की गई है।

(v) शक्ति नीति के ख(iv) के अंतर्गत लिंकेज के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों के लिए सीआईएल से क्रमश 4000 मेगावाट, 1600 मेगावाट, 2640 मेगावाट, 3299 मेगावाट और 1600 मेगावाट की क्षमता के लिए कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vi) शक्ति नीति के पैरा ख (v) के तहत लिंकेज के लिए 4500 मेगावाट की क्षमता के लिए सीआईएल से कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vii) शक्ति नीति के पैरा ख (viii)(क) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तिमाही लिंकेज नीलामी के 18 दौरों का आयोजन किया गया है जिसमें से सफल बोलीदाताओं द्वारा 72.29 मि.ट. की मात्रा बुकिंग की गई।

12. ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

उन केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) खविद्युत और गैर–विद्युत क्षेत्र दोनों, के निर्दिष्ट अंत्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश 08.02.2016 को जारी किए गए थे, जिन्हें कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत अनुसूची–III कोयला खदानें आवंटित की गई हैं और खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम, 1957) के तहत आवंटित कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे। ब्रिज लिंकेज केन्द्र तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्र की कोयले की आवश्यकता तथा संबद्ध आबंटित कोयला खान/ब्लॉक से उत्पादन शुरू करने के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करता है।

13. कोयले की धुलाई पर जोर

इस संबंध में, सीएमपीडीआई और बीसीसीएल के सहयोग से एनएमएल जमशेदपुर द्वारा "कार्बन वैल्यू की रिकवरी के लिए कोकिंग कोल वॉशरी के मिडलिंग और फाइन्स का प्रभावी उपयोग" नामक दो आर एंड डी परियोजनाएं; और बीसीसीएल के सहयोग से एनएमएल जमशेदपुर और सीएमपीडीआई रांची द्वारा "सिमुलेशन विश्लेषण के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड की कोकिंग कोल वॉशरी का परफोर्मेंस अध्ययन" प्रगति पर है और यह वित्त वर्ष 2023–24 में पूरा हो जाएगा। सीएमपीडीआई, एमसीएल और बीसीसीएल के सहयोग से आईआईटी खड़गपुर द्वारा "भौतिक और रासायनिक परिष्करण के माध्यम से उच्च राख भारतीय कोयले का उन्नयन" नामक एक अन्य आरएंडडी परियोजना भी प्रगति पर है और यह सितंबर 2024 तक पूरा होने वाली है।

धुले हुए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने मौजूदा वॉशरीज़ के नवीनीकरण के अलावा नई वॉशरीज़ की योजना बनाई है जो पहले से ही प्रचालन में हैं। वर्तमान में, सीआईएल के पास 13 कोयला वॉशरीज़ हैं, जिनमें से 10 कोकिंग कोल (3 हाल ही में कमीशन की गई कोकिंग कोल वॉशरीज़ सहित) और 3 नॉन–कोकिंग कोल वॉशरीज़ हैं, जिनकी कुल क्षमता क्रमशः 18.35 मि.ट. और 21 मि.ट. है। 3 गैर–कोकिंग कोल वॉशरियों में से, लखनपुर (10 एमटीवाई), एमसीएल को 15 अप्रैल, 2024 को चालू किया गया था।

अधिकांश मौजूदा वॉशरीज बहुत पुरानी हैं और अपने डिजाइन किए गए जीवन को पूरा कर चुकी हैं जिससे उनकी दक्षता कम हो गई है। सीआईएल ने टर्नकी विधि के माध्यम से अपने मौजूदा मूनीडीह वॉशरी (बीसीसीएल) के नवीकरण का कार्य सौंपा है। सीआईएल बीसीसीएल की 4 पुरानी और अक्षम वॉशरियों यानी दुग्दा–II, सुदामडीह, मधुबन और महुदा को निजी क्षेत्र के माध्यम से मौद्रीकृत करने की भी योजना बना रही है।

कोयले की धुलाई को और बढ़ावा देने के लिए सीआईएल में 8 नई आगामी कोकिंग कोयला वॉशरी परियोजनाएं हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

14. आग, धंसाव और पुनर्वास क्षेत्रों के समाधान के लिए मास्टर प्लान

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12.08.2009 को आग, धंसाव और संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों के पुनर्वास के दायरे के साथ मास्टर प्लान को अनुमोदित किया गया था। झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) में कार्यान्वयन की समय सीमा 12 वर्ष है जिसमें पूर्व–कार्यान्वयन गतिविधियों के 2 वर्ष शामिल हैं और अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार इसे 10 वर्षों के लिए रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए माना गया था। जेसीएफ के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि 11.08.2021 को समाप्त हो गई है और आरसीएफ के लिए 11.08.2019 को समाप्त हो गई है।

क. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लीजहोल्ड में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की संक्षिप्त स्थिति

आग से निपटना: झरिया कोलफील्ड में सतही कोयले की आग के चित्रण के लिए बीसीसीएल द्वारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के माध्यम से कोयला खान अग्नि सर्वेक्षण / अध्ययन की स्थापना की गई थी। 2017 की अपनी रिपोर्ट के अनुसार कुल 34 सक्रिय अग्नि स्थल थे। बीसीसीएल ने इन स्थलों में आग से निपटने के लिए कार्रवाई की है। एनआरएससी ने 2020–21 में आग का सर्वेक्षण किया है और 27 अग्नि स्थलों की उपस्थिति की सूचना दी है।

बीसीसीएल ने 2020–21 में सर्वेक्षण किए गए 27 राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) स्थानों पर कार्रवाई की है। इन 27 हिस्सों में से 16 आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। कार्य सौंप दिया गया है और 15 स्थानों पर कोयला निष्कर्षण शुरू कर दिया गया है। एक स्थान के लिए एमडीओ मोड पर परियोजना सौंपी गई है और प्रारंभिक कार्य चल रहे हैं। शेष 11 स्थानों में से, एनआरएससी (2021–22) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 10 स्थानों पर आग में कमी की प्रवृत्ति या मार्जिनल फायर दिखाई दी है और समग्र सतही अग्नि क्षेत्र घटकर 1.8 वर्ग किमी रह गया है। इसलिए इन स्थानों पर सरफेस ब्लैंकेटिंग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 10 स्थानों में से 8 स्थानों पर ब्लैंकेटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। शेष 1 स्थल पर आग का पता लगाने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाई गई है जिसके लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के लिए सीआईएल को प्रस्ताव भेजा गया है।

पुनर्वास : मास्टर प्लान के अनुसार 595 स्थलों में कुल 54,159 परिवारों का सर्वेक्षण किया जाना था। 2020 में जेआरडीए ने 595 स्थलों का सर्वेक्षण पूरा किया।

गैर एलटीएच परिवारों के पुनर्वास के लिए 18272 मकानों का निर्माण शुरू किया गया है जिनमें से 14874 मकान बेलगोरिया पुनर्वास टाउनशिप ''झरिया विहार'' में पूरे हो चुके हैं जिनमें से 5035 मकान आबंटित किए गए हैं और 2827 परिवारों (गैर एलटीएच) को प्रभावित क्षेत्रों से नए मकानों में स्थानांतरित किया गया है।

अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए, निर्माण के लिए लिए गए 15713 घरों में से 11944 घरों को पूरा कर लिया गया है और इन घरों में 4436 बीसीसीएल कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

बीसीसीएल बोर्ड ने गैर–बीसीसीएल परिवारों के लिए जेआरडीए को 8,000 घर सौंपने का निर्णय लिया है और इसके बारे में जेआरडीए को अवगत करा दिया गया है।

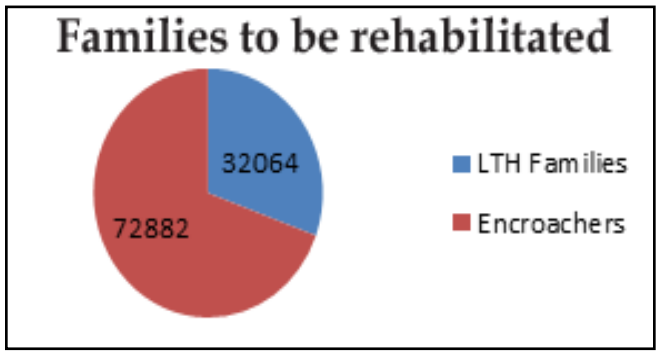

संशोधित झरिया मास्टर प्लानः

मास्टर प्लान का कार्यकाल पूरा होने के कारण, चालू गतिविधियों को जारी रखने के लिए, मास्टर प्लान के समय विस्तार के प्रस्ताव की जांच की गई और कोयला मंत्रालय ने "प्रतिबद्ध कार्यों" के लिए एक वर्ष के लिए विस्तार दिया। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिव के निदेश के अनुसार, निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 25 अगस्त,2021 को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हितधारकों के साथ बातचीत की। समिति द्वारा झरिया मास्टर प्लान के लिए आगे का रास्ता तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर कोयला मंत्रालय ने संशोधित झरिया मास्टर प्लान तैयार किया और अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल सचिव को भेजा।

15. भूमि पुनरुद्धार के लिए उपग्रह निगरानी

सतत विकास के लिए खनन क्षेत्रों का पुनरुद्धार महत्वपूर्ण है। उचित सुधार पर जोर दिया जा रहा है जिसमें तकनीकी और जैविक सुधार के साथ–साथ खान को बंद करना शामिल है। भूमि सुधार के लिए उपग्रह निगरानी पर अपेक्षित जोर दिया जा रहा है ताकि भूमि सुधार की प्रगतिशील स्थिति का आकलन किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हो, किए जा सकें।

दो श्रेणियों में आने वाली खानों के लिए सैटेलाइट डाटा के आधार पर सीआईएल खानों की भूमि पुनरुद्धार की निगरानी की जा रही है:

(क) प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) एमसीएम से अधिक उत्पादन करने वाली खानें। प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) से अधिक के अंतर्गत आने वाली खानों/क्लस्टर की वार्षिक आधार पर निगरानी की जाती है

(ख) 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) एमसीएम प्रति वर्ष से कम उत्पादन करने वाली खानें। 5 एमसीएम (कोयला+ओबी) प्रति वर्ष श्रेणी से कम के अंतर्गत आने वाली खानों/क्लस्टरों की चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों के अंतराल पर निगरानी की जाती है।

वर्ष 2023–2024 में, कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों के तहत कुल 121 परियोजनाओं की भूमि सुधार निगरानी, जिसमें 76 ओपनकास्ट परियोजनाएं शामिल हैं, जो प्रति वर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से अधिक उत्पादन करती हैं और 45 ओपनकास्ट परियोजनाएं / क्लस्टर / यूजी खानें जो प्रतिवर्ष 5 एमसीएम (कोयला + ओबी) से कम उत्पादन करती हैं।), को निगरानी के लिए लिया गया है। सैटेलाइट डाटा का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग निर्धारित समय पर पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट संबंधित सहायक कंपनी/सीआईएल को प्रस्तुत की जा चुकी है।

ड्रोन आधारित सर्वेक्षण

सीएमपीडीआई के पास दो सर्वे ग्रेड ड्रोन थे जो लिडार, ऑप्टिकल और थर्मल सेंसर से लैस हैं। सीएमपीडीआई ने हाल ही में एक नया फिक्स्ड विंग वीटीओएल ड्रोन/यूएवी हासिल किया है, जो ड्रोन के अपने बेड़े को और मजबूत करता है। इन ड्रोन/यूएवी का उपयोग वर्तमान में प्राप्त आवश्यकता

के अनुसार सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, सीएमपीडीआई द्वारा पैनल में शामिल बारह (12) ड्रोन सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का भी नियमित आधार पर उपयोग किया जा रहा है। 2023–24 में पूरे किए गए कुछ प्रमुख ड्रोन/यूएवी सर्वेक्षण कार्य इस प्रकार हैं:

- सीएमपीडीआई ने कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार नीलामी के 8वें/9वें दौर के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के वीडियो तैयार करने के लिए नीलाम किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों के लिए ड्रोन आधारित स्थलाकृतिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है। यह संभावित बोलीदाताओं को क्षेत्र की बेहतर समझ और जल्द से जल्द ब्लॉक के विकास के लिए योजना बनाने के लिए पूरे ब्लॉक क्षेत्र का एक विहंगम दृश्य प्रदान करेगा। पहले चरण में, ड्रोन सर्वेक्षण और 38 कोयला ब्लॉकों के लिए आउटपुट डेटा प्रस्तुत करना जनवरी 2024 तक पूरा हो गया। दूसरे चरण में, ड्रोन सर्वेक्षण और 21 कोयला ब्लॉकों का आउटपुट डेटा प्रस्तुत करना मार्च, 2024 तक पूरा हो गया। तीसरे चरण में, ड्रोन सर्वेक्षण और 8 कोयला ब्लॉकों के लिए आउटपुट डेटा प्रस्तुत करना मार्च, 2024 तक पूरा हो गया।
- सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में नॉर्थ कर्णपुरा और साउथ करनपुरा कोलफील्ड्स में मैपिंग के लिए ड्रोन सर्वे मार्च, 2024 में शुरू हो गया है और काम चल रहा है।
- (i) कल्याणेश्वरी, रामनगर, विक्टोरिया और सीतारामपुर ब्लॉक, रानीगंज कोलफील्ड, ईसीएल, पश्चिम बंगाल और (ii) राजरप्पा ओसीपी, सीसीएल, रामगढ़, झारखंड में फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करके हाई रेजुल्यूशन ऑर्थो–फोटो मोज़ेक इमेज और स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करना।
- छाल और बरूद, एसईसीएल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ में मृदा नमी संरक्षण (एसएमसी) अध्ययन के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र और हाई रेजुल्यूशन ऑर्थो–फोटो मोज़ेक जेनरेशन।
- गारे पेलमा IV/2 और IV/3 ब्लॉक, एसईसीएल, एमपी में बुनियादी ढांचे का मानचित्रण।
- उरीमरी परियोजना, सीसीएल में फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करके पुराने ओबी डंप पर स्थलाकृति और वॉल्यूमेट्रिक सर्वेक्षण।
- नीति आयोग के निर्देशानुसार सीसीएल की परित्यक्त खदानों में ड्रोन सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और आउटपुट सीसीएल को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- रानीगंज सीएफ, ईसीएल के तहत, कबितीर्थ ब्लॉक और तातापाकी रामकोला कोलफील्ड, एसईसीएल के तहत सेंदुर ब्लॉक के लिए नीलामी के 8वें दौर में नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए खान डोजियर तैयार करने से संबद्ध हाई रेजुल्यूशन ऑर्थो–फोटो मॉजेक इमेज और संबद्ध डीजीपीएस सर्वेक्षण।
- पर्यावरण विभाग सीसीएल के संबंध में पुंडी ओसीपी की परियोजना के रियल टाइम हवाई फुटेज और वीडियो तैयार करने के लिए यूएवी से डेटा प्राप्त करना।
- वॉशरी स्थल के चयन के लिए राजरप्पा ओसीपी, सीसीएल में यूएवी आधारित ऑप्टिकल सेंसर द्वारा डेटा की प्राप्ति।

भूमि पुनरुद्धार, एनएलसी के लिए उपग्रह निगरानी:

1. **जोखिम भरे क्षेत्रों में सुरक्षा और निगरानी**– एनएलसीआईएल के पास 259 वर्ग किलोमीटर लीज्ड होल्ड एरिया है और पुराना डंप और वनीकरण क्षेत्र है जिसे मानव जाति की सुरक्षा के लिए निगरानी की आवश्यकता है। एनएलसीआईएल यूएवी और एलआईडीएआर संयोजन के साथ समय–समय पर इस क्षेत्र की नियमित निगरानी करना शुरू कर रहा है।
2. **टाइम–लैप्स फोटोग्राफी**– आरजीबी ड्रोन का उपयोग शुरू किया गया, एनएलसीआईएल खानों और थर्मल की फोटोग्राफी समय–समय पर की जा रही है।
3. **स्टॉकपाइल इन्वेंट्री को मापना** – लिग्नाइट/कोयला स्टॉक मापन के लिए लिडार/आरजीबी

आरटीके/पीपीके सक्षम ड्रोन का उपयोग करने के लिए एनएलसीआईएल ने एक प्रायोगिक के रूप में शुरुआत की।

4. **साइट मैपिंग**– खानों और पुराने डंप की साइट मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

16. सीआईएल तथा एससीसीएल के उत्पादकता मानदंडों – आउटपुट प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) की समीक्षा

(टन में)

वर्ष	कोल इंडिया लिमिटेड			सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र	यूजी	ओसी	समग्र
2017-18	0.86	13.15	7.44	1.08	13.73	4.89
2018-19	0.95	14.68	8.51	1.40	16.94	6.23
2019-20	0.99	14.25	8.53	1.44	16.57	6.37
2020-21	0.93	15.09	9.02	0.92	13.86	5.62
2021-22	0.97	15.46	9.56	1.19	15.15	6.09
2022-23	1.05	22.04	12.80	1.27	13.94	5.31
2023-24 (अनंतिम)	1.18	25.43	13.43	1.19	13.24	5.42

17. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीपीआर) के संबंध में नीतिगत पहल और सुधार के उपाय

17.1 कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल):– चालू वित्त वर्ष के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं/गतिविधियों को शुरू किया है, जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के मौजूदा दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। वित्त वर्ष 23–24 और पिछले तीन वर्षों के दौरान सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर निधि और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआईएल और सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर बजट और व्यय								
कंपनी	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय
ईसीएल	8.84	11.56	12.57	13.86	0.00	6.92	0.00	7.33
बीसीसीएल	0.00	6.12	0.00	2.99	0.00	11.42	0.00	7.77
सीसीएल	46.46	56.60	50.25	24.82	46.27	36.12	51.68	61.91
डब्ल्यूसीएल	0.00	5.95	1.08	12.54	8.44	11.62	11.75	13.97
एसईसीएल	79.42	38.33	67.58	69.34	44.69	59.28	51.41	53.07
एमसीएल	168.44	205.34	181.62	251.76	195.86	207.97	142.31	162.89
एनसीएल	118.23	129.93	132.75	123.52	132.14	133.64	148.92	157.87
सीएमपीडीआईएल	4.65	4.66	6.61	6.86	7.30	8.92	7.66	8.81
सीआईएल	8.47	95.36	6.81	77.64	7.10	42.04	11.30	98.56
कुल	**434.51**	**553.85**	**459.27**	**583.32**	**441.80**	**517.93**	**425.03**	**572.18**

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, चालू वर्ष के लिए प्राथमिकता प्राप्त विषय 'स्वास्थ्य और पोषण' हैं। इसके अलावा, कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्तीय वर्ष 23–24 के दौरान शुरू की गई/कार्यान्वित की जा रही प्रमुख सीएसआर गतिविधियां/परियोजनाएं निम्नानुसार है:

I. थैलेसीमिया बाल सेवा योजना (टीबीएसवाई) का तीसरा चरण, सीआईएल की फ्लैगशिप परियोजना मई 2023 में माननीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तीसरे चरण में 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और इसमें थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के कम से कम 300 रोगियों को कवर किया जाएगा।

II. सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनी में बहु कौशल विकास संस्थानों (एमएसडीआई) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पहले एमएसडीआई का उद्घाटन 'फैशनप्रेन्योर' ट्रेड के लिए बीसीसीएल द्वारा बेलघरिया, धनबाद में किया गया है।

III. पबित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एमसीएल द्वारा तालचेर, ओडिशा में 493 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 500 बिस्तरों वाला अस्पताल सह 100 सीट वाला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन दिसंबर 2023 में किया गया था।

IV. संयुक्त रूप से सीआईएल और सीसीएल ने 25–26 अप्रैल 2023 को रांची में एक सीएसआर कॉन्क्लेव "री–इंजीनियरिंग सीएसआर" का सफलतापूर्वक आयोजन किया। छह विचारक नेताओं ने दर्शकों के साथ अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। लगभग 300 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें कंपनी के शीर्ष प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी, सीआईएल के सीएसआर अधिकारी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्र शामिल थे।

V. सीएसआर एमआईएस को सीआईएल के ईआरपी मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया था और ईआरपी के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों का रिकॉर्ड–रखरखाव शुरू हो गया है।

VI. झारखंड के 11 कोयला खनन जिलों के हाई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी लैब की स्थापना द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल को भारत के अन्य हिस्सों में भी दोहराया गया। परियोजना का कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है।

VII. खनन क्षेत्र के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल जैसे शेफ, इलेक्ट्रीशियन आदि में प्रशिक्षित करने के लिए एक परियोजना टाटा स्ट्राइव के साथ शुरू की गई थी।

VIII. प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल मार्च 2024 में झारखंड के 4 जिलों में जन्मजात हृदय रोग (सीएचडी) रोगियों के लिए एक व्यापक पहल के रूप में शुरू किया गया था।

IX. सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सिविल सेवा उम्मीदवारों की आर्थिक सहायता के लिए एनआईआरएमएएन (राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने के लिए नेक पहल) 7 मार्च 2024 को माननीय मंत्री (कोयला) द्वारा शुरू किया गया था।

X. आईआईटी, बॉम्बे और एनआईटी, राउरकेला में लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू की गईं।

XI. जेईई, एनईईटी आदि जैसी विभिन्न परीक्षाओं के लिए वंचित छात्रों को कोचिंग में सहायता सीआईएल, डब्ल्यूसीएल (तराश सुपर 30) और एसईसीएल (एसईसीएल के सुश्रुत) द्वारा अपने सीसीएल के लाल/लाडली परियोजना के माध्यम से स्थापित सीसीएल की सर्वोत्तम पद्धति को दोहराने के प्रयास के रूप में शुरू की गई थी।

XII. सीआईएल ने न्यूरोसाइंस संस्थान, कोलकाता में न्यूरो रोगियों के लिए एमआरआई मशीन प्रदान की।

पुरस्कार और सराहना

थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, जो सीआईएल की एक फ्लैगशिप सीएसआर पहल है, ने ब्राजील में 25 मार्च 2024 को 'द ग्रीन ऑर्गनाइजेशन' द्वारा प्रस्तुत 'ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स' 2024 की सीएसआर श्रेणी में 'ईंधन, बिजली और ऊर्जा' क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता है। 500 रोगियों के उपलब्धि का 7 मार्च 2024 को नई दिल्ली में माननीय मंत्री (कोयला) द्वारा स्मरणोत्सव मनाया गया था।

17.2 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

आज की तारीख तक 20 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत वाली 14 कोयला परियोजनाएं चल रही हैं, जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। चालू परियोजनाओं की विभिन्न उपलब्धियों की स्थिति को निगरानी के लिए एमडीएमएस पोर्टल (सीएमपीडीआई द्वारा विकसित) और ई–सीपीएमपी (ऑनलाइन कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल) और ओसीएमएस पोर्टल (एमओएसपीआई) में राज्य स्तर पर और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ लंबित मुद्दों को हल करने के लिए अपलोड किया जा रहा है।

17.2.1 एससीसीएल द्वारा कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

वर्तमान में, एससीसीएल तेलंगाना राज्य में 39 खानों (22–भूमिगत और 17–ओपनकास्ट) का प्रचालन कर रही है। ओडिशा राज्य में एससीसीएल को आवंटित नैनी कोयला खान वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू होने की उम्मीद है। एससीसीएल ने 2024–25 के अंत तक उत्पादन बढ़ाकर 77 मि.ट. करने की परिकल्पना की है। उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –

- 7 नई खानें खोलने की योजना (जीवीसीएफ में 6 और तालचेर में 1)
- कोयला निकासी अवसंरचना सुविधा में सुधारः एससीसीएल अपने सीएचपी में बदलाव कर रहा है, नए सीएचपी, क्रशर का निर्माण कर रहा है।
- कोयले की निकासी के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण और नई रेल लाइनें बिछाना।
- प्रेषण स्थल तक छोटी दूरी के कोयले के परिवहन के लिए सड़कों का विकास।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एससीसीएल का सीएसआर बजट और व्यय (आंकड़े करोड़ रुपये में)										
कंपनी	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2022-23	
	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय	सांविधिक प्रावधान	व्यय
एससीसीएल	34.86	34.86	47.98	59.67	43.04	31.85	35.82	21.38	37.50	7.18

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार उपायः एससीसीएल

1. एससीसीएल ने बड़े पैमाने पर समुदायों और समाज के लाभ के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां शुरू की हैं। एससीसीएल ने कोविड और बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा को बढ़ावा देने, बेरोजगार युवाओं में कौशल प्रशिक्षण, अनाथालयों और वृद्धाश्रमों को सहायता देने, खेल–कूद, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास कार्यों जैसे सड़कों, नालियां बिछाने, सामुदायिक भवनों का निर्माण, सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था आदि जैसे ग्रामीण विकास कार्यों, आपदा प्रबंधन कार्यकलापों आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर रहा है।
2. वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, एससीसीएल को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर के तहत 37.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करनी है। विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए 38.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई और व्यय राशि 7.18 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान एससीसीएल द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

3. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, जयशंकर भूपालपल्ली और मुलुगु ज़िलों में बाढ़ राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

4. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एससीसीएल परिचालन जिलों में बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 1.01 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

5. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एससीसीएल सीएसआर के तहत तेलंगाना राज्य के 119 निर्वाचन क्षेत्रों में डॉ. बीआर अम्बेडकर ज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

6. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, मंचेरियल जिले के लक्सेट्टीपेट गांव में सरकारी जेडपीएच स्कूल और सरकारी जूनियर कॉलेज को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

7. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, काकतीत्य विश्वविद्यालय, कोठागुडेम को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2.97 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

8. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एससीसीएल सीएसआर के तहत येलंडु क्षेत्र में 10 बोर–वेल प्रदान करने के लिए 13.75 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

9. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एससीसीएल सीएसआर के तहत गोदावरीखानी में दिव्यांग बच्चों के लिए स्थापित मनोचैतन्य संस्थान के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

10. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बेल्लमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में सामुदायिक भवनों के निर्माण, सड़कें बिछाने और ओपन जिम, हाई–मास्ट लाइटिंग जैसे ग्रामीण विकास कार्यों को प्रदान करने के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

11. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, एससीसीएल सीएसआर के माध्यम से एससीसीएल परिचालन क्षेत्रों के परिधीय गांवों में स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करने के लिए 3.48 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

12. भद्राचलम में बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट बांटना।

13 भद्राचलम में बाढ़ पीड़ितों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन

14 एससीसीएल क्षेत्रों में सेना/पुलिस भर्ती के लिए बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

15 हर घर तिरंगा – एससीसीएल क्षेत्रों में लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण और इसे फहराना

17.3 एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधार उपायः

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) सीएसआर नीति के तहत विभिन्न सतत विकास गतिविधियों और कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन कर रहा है। 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर के तहत धन का आवंटन किया गया है। ये दिशा–निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) पर आधारित हैं, जिसमें पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया है।

पिछले 10 वर्षों में उन परियोजनाओं का विवरण जिनकी लागत 10 करोड़ (वर्ष–वार) से अधिक है।

एनएलसीआईएल (समेकित) – सीएसआर			
क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	विवरण	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1	2015-16	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत सरकारी स्कूलों (तमिलनाडु और राजस्थान) में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	36.72
2	2019-20	पीएम केयर्स फंड	20.00
3	2020-23	दक्षिण रेलवे में तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों के सर्कुलेटिंग एरिया में सार्वजनिक शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	42.55
4	2019-24 (एनयूपीपीएल)	उत्तर रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में 71 प्रीफैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण।	16.17

17.3.1 सीएसआर मिशन विवरणः

कंपनी के मिशन के अनुरूप, एनएलसीआईएल अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके समाज में वंचित लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना जारी रखेगा और गरीबी उन्मूलन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय और पारदर्शी संगठन होगा।

एनएलसीआईएल कंपनी की लगभग सभी सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए एक परियोजना–आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों के समूह आवश्यकता मूल्यांकन, आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी, परियोजनाओं को सौंपना, प्रभाव मूल्यांकन और सततता से लेकर सीएसआर परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों में शामिल हैं। लगभग 10 वर्षों से, एनएलसीआईएल का सीएसआर कार्य एक अलग सीएसआर विभाग के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग में तकनीकी विशेषज्ञता और सामुदायिक विकास में सामाजिक कार्य आदि से लेकर क्रॉस फंक्शनल दक्षताओं वाले पेशेवर शामिल हैं।

17.3.2 एनएलसीआईएल का सीएसआर सिद्धांतः

एनएलसीआईएल का मानना है कि लाभ, लोगों और ग्रह के सिद्धांतों को शामिल करने के अलावा व्यवसाय करने का कोई स्थायी विकल्प नहीं है, इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव (ट्रिपल बॉटम लाइन दृष्टिकोण) के संदर्भ में प्रदर्शन को मापा जाता है।

सीपीएसई के रूप में, एनएलसीआईएल स्वच्छ विद्युत पैदा करने, कार्यस्थल और पर्यावरण में प्रदूषण को नियंत्रित करने और निरंतर सीएसआर कार्यक्रमों के साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण प्रबंधन उपायों को परिश्रमपूर्वक आगे बढ़ाएगा और उन्हें लागू करेगा।

सीएसआर कार्यों के माध्यम से कुछ अलग करना – सफलता की कहानियां

1. **जलपर्याप्तता 'सतत जल संसाधन संवर्धन'**– सीएसआर परियोजना की प्रासंगिक पृष्ठभूमिः

ऐतिहासिक रूप से, झीलों को आसपास के समुदायों द्वारा प्रबंधित किया गया है, कभी–कभी इसे स्थानीय प्रशासकों के प्रशासनिक और वित्तीय सहायता से भी प्रबंधित किया जाता

है। बाद में, इस सामायिक निर्धारित भूमिका को औपचारिक प्रशासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

तमिलनाडु की स्थलाकृति में आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून से बारिश होती है और विशेष रूप से कुड्डालोर जिले में अधिकतम वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। सामान्यतः एक वर्ष में होने वाली कुल वर्षा 1350 मिमी की औसत वर्षा 1200 मिमी से 1600 मिमी तक होती है।

जब पिछले वर्षों में सामान्य वर्षा हुई थी, उस अवधि के दौरान कुछ वृद्धि और गिरावट देखी गई थी (हालांकि 1996 में 2126 मिमी वर्षा के साथ बाढ़ आ गई थी)। नवम्बर, 2015 के दौरान अचानक आई बाढ़ के कारण कुड्डालोर जिला पूरी तरह डूब गया है। 09/11/2015 को 454 मिमी की उच्चतम वर्षा के कारण यह स्थिति और खराब हो गई, जो 50 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा थी। लेकिन इसके विपरीत, 2016 के दौरान कम बारिश दर्ज की गई थी और जिले में 2016 के दौरान दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून दोनों में और 2017 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून में भी मामूली वर्षा हुई है।

कुड्डालोर जिले में मानसूनी वर्षा की दयनीय विफलता के कारण लोगों को सुरक्षित पेयजल, घरेलू उपभोग, पशुधन और सिंचाई की उपलब्धता के संदर्भ में अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई होती है। जब स्थिति का विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि कुड्डालोर जिले में जल निकायों को 50 से 100 वर्षों से अधिक समय से डिसिल्ट नहीं किया गया है और इसलिए गाद की वजह से जल निकायों की क्षमता कम हो गई है।

इस चुनौती से निपटने के लिए, एनएलसीआईएल ने सीएसआर के तहत अपने आसपास और परिचालन क्षेत्रों में सतत जल संवर्धन संसाधनों को विकसित करने के लिए अथक प्रयास किया है। इस कार्य में जल निकायों से गाद निकालना और इन्हें गहरा करना, पानी की वृद्धि, वर्षा जल संचयन, सिंचाई और भूमिगत रिचार्जिंग, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरणीय संधारणीयता, बांधों को मजबूत करना, स्लुइस और रेगुलेटर का निर्माण, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बांधों के साथ वृक्षारोपण, इन झीलों में सौर ऊर्जा संचालित पंप स्थापित करना और ग्रामीण विकास की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

कार्यान्वयन के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियां:

- जल निकाय, तालाबों और टैंकों का सर्वेक्षण
- जलाशयों/तालाबों से गाद निकालना
- बांधों का सुदृढ़ीकरण और स्लुइस और रेगुलेटरों का निर्माण
- बोरवेल खोदना और सौर ऊर्जा संचालित मोटर पंप स्थापित करना
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी
- गाद रहित तालाबों की जियो–टैगिंग
- क्षमता निर्माण, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकनः
- पुनरुद्धारित झील को संबंधित हितधारकों को सौंपनाः

संचालन के आसपास के आसपास सतत इको–सिस्टम, वनस्पतियों और जीवों को सुनिश्चित करने के लिए, सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल ने वित्त वर्ष 2014–15 से वित्त वर्ष 2020–21 तक ग्रामीण विकास के तहत अकेले जल संसाधन संवर्धन परियोजनाओं के लिए 61.53 करोड़ रुपये खर्च किए।

परियोजना का प्रभावः

- वित्त वर्ष 2014–15 से सीएसआर के तहत अब तक 43 निकायों/तालाबों से गाद निकाली गई है, जिससे तमिलनाडु में कुड्डालोर जिले (28), कोयंबटूर (1), धर्मपुरी (1), राजस्थान में बीकानेर जिले (3) और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश के 300 से अधिक गांवों में 379968 से अधिक आबादी लाभान्वित हुई है।
- भूमिगत जल स्तर में वृद्धि।
- ग्रामीणों की आजीविका बढ़ने से गांवों से शहरों की ओर पलायन कम हुआ
- सिंचाई के लिए पानी की बेहतर पहुंच और उपलब्धता
- बेहतर बाढ़ नियंत्रण और स्लुइस/रेगुलेटरों तक पहुंच के लिए बांधों को सुदृढ़ किया गया।
- इस क्षेत्र में पशुधन संख्या में सुधार
- बेहतर मत्स्य पालन एवं एक्वा–कल्चर

- फसल की पैदावार में वृद्धि और इससे किसानों की कमाई के स्तर में सुधार होना।
- आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर में सराहनीय वृद्धि होगी।
- धान, गन्ना और अन्य फसलों अर्थात धान, गन्ना, जॉक फ्रूट, काजू, तिल, उड़द आदि इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं, जिनके लिए जल सुरक्षा के माध्यम से बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
- वालाजाह झीलः सिंचाई क्षेत्र 24700 एकड़, 22500 घर और 90000 से अधिक आबादी लाभान्वित हो रही है।

एनएलसीआईएल की सीएसआर आउटरीच टीमों ने सामुदायिक जल निकायों और झील प्रणाली के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बातचीत और अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को संगठित करना शुरू किया। स्थानीय समुदायों ने अपने गांव के तालाबों को बचाने के लिए कदम बढ़ाया।

2. निवारक स्वास्थ्य देखभाल

सभी उम्र में सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। खराब स्वच्छता की स्थिति और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी समाज में वंचित और गरीब लोगों की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने और गांवों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल ने परिचालन क्षेत्रों में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण पर कार्य करने के लिए पिछले 10 वर्षों में 229.16 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य जांच शिविरः

एनएलसीआईएल आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए न्यूनतम 10 चिकित्सा शिविर आयोजित करता है और 12 रक्तदान शिविर आयोजित करता है। नेयवेली के आसपास के गांवों में लगभग 30000 जरूरतमंद आबादी हर साल स्वास्थ्य शिविरों से लाभान्वित होती है। गर्भवती ग्रामीण महिलाओं में रक्ताल्पता, शिशुओं में जन्म के समय कम वजन और अतिसार रोगों की रोकथाम, वृद्ध जनसंख्या में मोतियाबिंद की रोकथाम, विभिन्न संचारी और गैर–संचारी रोगों के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करने के लिए एक बहु–रूपात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। मेडिकल टीम जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, बाल रोग, त्वचा विज्ञान, पल्मोनोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ शामिल हैं, सामुदायिक आउटरीच मोड के माध्यम से व्यापक उपचार प्रदान करने की दिशा में मल्टी–मोडल मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करनाः

सार्वजनिक सेवाओं में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की पहुंच और उपलब्धता के बीच अंतर को दूर करने के लिए, एनएलसीआईएल ने सीएसआर के तहत कई कार्य किए हैं।

ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापनाः

भारत में कोविड–19 की दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ रहा था और पूरे देश में सकारात्मक मामलों की संख्या बढ़ रही थी। रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्राथमिकता का पहलू बन गई है। एनएलसीआईएल ने कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए सीएसआर के तहत कई सक्रिय निवारक और शमन उपाय किए थे।

कंपनी ने कोविड–19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों के अनुरूप तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक राज्यों के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 2100 से अधिक रोगियों की ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए 21 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। कोविड–19 के खिलाफ लड़ने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मदद करने के उद्देश्य से, सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल ने **तमिलनाडु, मणिपुर, ओडिशा, यूपी और राजस्थान राज्यों में विभिन्न सरकारी अस्पतालों को 360 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वितरित किए।**

जिला सरकारी अस्पताल, कुड्डालोर में डायलिसिस केंद्रः

एनएलसीआईएल ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 2.25 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से कुड्डालोर के जिला सरकारी अस्पताल में 13 डायलिसिस मशीनों के साथ संबद्ध सुविधाओं वाली अत्याधुनिक किडनी डायलिसिस सुविधा की स्थापना की और इन्हें जरूरतमंद रोगियों की आगे की सेवाओं के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया। किडनी के करीब 50 मरीज रोजाना डायलिसिस करा रहे हैं।

कुड्डालोर जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य अवसंरचना विकसित की गई अर्थात सरकारी पीएचसी पालकोल्लाई, इरुप्पु और पनरुती में रोगी प्रतीक्षालय, शौचालय, अप्रोच सड़क आदि का निर्माण किया गया और हर साल आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अस्पतालों को चिकित्सा स्वास्थ्य उपकरण प्रदान किए गए। इन कार्यों से 50,000 से अधिक आबादी लाभान्वित हो रही है। सरकारी अस्पताल कुर्नजीपाडी में ट्रॉमा केयर सेंटर का निर्माण किया गया। जिससे 2,26,000 आम जनता को लाभ हुआ और कुड्डालोर में टीबी अस्पताल का निर्माण किया ताकि हर साल 5,000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना

अपने परिचालन नेयवेली क्षेत्र में वंचित वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, एनएलसीआईएल ने कुड्डालोर जिले के नेयवेली में 5000 से अधिक जरूरतमंद स्कूली बच्चों के लाभ के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। सीएसआर के तहत एनएलसीआईएल ने परिचालन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के कार्यों के लिए पिछले 10 वर्षों में 154.01 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

एनएलसीआईएल अपने 10 स्कूलों (3 हायर सेकेंडरी स्कूल, 2 हाई स्कूल, 3 मिडिल स्कूल और 2 एलीमेंट्री स्कूल) में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करता है। इन 11 स्कूलों में छात्रों की संख्या 5460 थी। कंपनी ने 3 एनएलसी हायर सेकेंडरी स्कूलों के कक्षा XI और XII के छात्रों के लिए ब्रेकफास्ट योजना लागू की ताकि छात्र सुबह की विशेष कक्षाओं में भाग ले सकें, सार्वजनिक परीक्षाओं में उपस्थिति और प्रदर्शन में सुधार हो सके, जिससे लगभग 2000 छात्र लाभान्वित होंगे।

एनएलसी स्कूलों में बालिकाओं की संख्या कुल 5500 में से 3250 है। कुल में से 95% नेयवेली आसपास के क्षेत्रों से है। कक्षा ९ और ग्प् के छात्रों को हर साल एक लाभ के रूप में स्कूल वर्दी मुफ्त प्रदान की जाती है ताकि उन्हें हायर सेकंड स्तर के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 33 इन्सिनरेटर (सेनेटरी नैपकिन डेस्ट्रोयर) उन सभी एनएलसी स्कूलों में उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें छात्राएं पढ़ रही हैं। नेयवेली स्कूलों की छात्राओं में स्कूल टॉपर्स को हर साल 10,000 रुपये नकद पुरस्कार + मेरिट प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए गए। छात्रों को स्काउट्स और गाइड फोरम में नामांकित किया जाता है जिसमें नेयवेली स्कूलों की 100 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। एनएलसीआईएल ने जवाहर साइंस कॉलेज नेयवेली के एससी और एसटी और ओबीसी छात्रों को कला और विज्ञान में डिग्री हासिल करने के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की है जो एनएलसीआईएल द्वारा संचालित है।

विशेष शिक्षा: मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए स्थापित एनएलसी (इंडिया) लिमिटेड के सीएसआर का केंद्र स्नेह ऑपोर्च्यूनिटी स्कूल (एसओएस) अप्रैल 1987 से मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर और प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रशिक्षित और सहायता करने हेतु कार्य कर रहा है, ताकि उनका कौशल बढ़ाकर समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। स्कूल का उद्देश्य विशेष बच्चों को मुफ्त में डेकेयर, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करना है। स्कूल की नियमित गतिविधियां विशेष बच्चों को डे केयर, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। विभिन्न विकलांगताओं (मानसिक मंदता, श्रवण बाधिता के साथ प्रमस्तिष्क पक्षाघात, एमआर, दृश्य बाधित, ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम) वाले कुल 70 बच्चे इन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

स्कूल का बुनियादी ढांचा:

एनएलसीआईएल ने स्कूली बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं

को सुविधाजनक बनाकर ग्रेड विशिष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से नेयवेली और उसके आसपास के विभिन्न सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की। 15,000 से अधिक स्कूली बच्चों के लाभ के लिए अब तक 27 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। अब तक लगभग 60 स्कूलों और सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है। स्वच्छ विद्यालय अभियान परियोजना के तहत तमिलनाडु राज्य में 577 स्कूलों में 1528 शौचालय ब्लॉकों और राजस्थान राज्य में 71 स्कूलों में 108 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया।

एनयूपीपीएलः उत्तर प्रदेश

4. उत्तर रेलवे के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में 80 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण करके स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना।

परिचय

उत्तर रेलवे, मैसर्स राइट्स और एनयूपीपीएल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी में, एक परिवर्तनकारी परियोजना सामने आई। उत्तर रेलवे नेटवर्क के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में 20.02 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 80 प्रीफैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण न केवल एक तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि सफल कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) सहयोग का एक उदाहरण भी स्थापित करता है।

पृष्ठभूमिः

स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है और सार्वजनिक स्वच्छता और सुविधा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में, रेलवे स्टेशन प्रतिदिन लाखों यात्रियों के लिए सेंट्रल हब हैं। हालांकि, अच्छे रख–रखाव की सुविधा वाले शौचालयों की कमी अक्सर यात्रियों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। उत्तर रेलवे ने मैसर्स राइट्स और एनयूपीपीएल सीएसआर के साथ साझेदारी में अपने नेटवर्क में 80 प्रीफैब्रिकेटेड टॉयलेट ब्लॉक बनाने के मिशन को शुरू करके इस परिदृश्य को बदलने का लक्ष्य रखा है।

परियोजना निष्पादनः

इस परियोजना की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी और भागीदारों अर्थात उत्तर रेलवे, मैसर्स राइट्स और एनयूपीपीएल के साथ विभिन्न चरणों में निष्पादित की गई थीः

आवश्यकताओं का आकलनः परियोजना एक व्यापक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के साथ शुरू हुईए जिसमें शौचालय ब्लॉकों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की गई। इन साइटों को यात्रियों की संख्या और मौजूदा सुविधाओं जैसे कारकों के आधार पर चुना गया था।

डिजाइन और प्रीफैब्रिकेशनः एक बार साइटों को अंतिम रूप देने के बादए शौचालय ब्लॉकों का डिजाइन और प्रीफैब्रिकेशन ऑफ–साइट हो गया। प्रीफैब्रिकेशन ने कम निर्माण समय, लागत–प्रभावशीलता और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण सहित कई फायदे प्रदान किए।

स्थल स्थापनाः निर्माण के बाद, पूर्वनिर्मित शौचालय ब्लॉकों को उनके संबंधित रेलवे स्टेशनों पर ले जाया गया। स्टेशन संचालन में न्यूनतम व्यवधान के साथ स्थापना प्रक्रिया तेज थी।

बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँः इन शौचालय ब्लॉकों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत बुनियादी ढाँचे और उपयोगिताओं जैसे पानी की आपूर्ति, सीवेज और बिजली को रेलवे स्टेशन की मौजूदा प्रणालियों में समेकित रूप से एकीकृत किया गया था।

रखरखाव और स्वच्छताः शौचालय ब्लॉकों को मूल स्थिति में रखने के लिए एक व्यापक रखरखाव योजना स्थापित की गई थी। इसमें नियमित सफाई, स्वच्छता और मरम्मत, यात्रियों के लिए उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना शामिल था।

लक्ष्य समूह

लक्ष्य समूह इन रेलवे स्टेशनों के माध्यम से आने–जाने वाले दैनिक यात्री, रेलवे पुरुष और महिला कर्मचारी हैं।

स्थान

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद, लखनऊ और दिल्ली मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशन

सफलता कारक:

गति और दक्षता: प्रिफैब्रिकेटिड निर्माण तकनीकों के उपयोग से परियोजना तेजी से शुरु हो सकीए स्टेशन संचालन में व्यवधान पैदा किए बिना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का समाधान किया।

बेहतर यात्री अनुभव: नवनिर्मित शौचालय ब्लॉकों ने रेलवे स्टेशनों पर कुल मिलाकर यात्री अनुभव में काफी सुधार कियाए जिससे उनकी यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और आराम में वृद्धि हुई।

बढ़ी हुई सार्वजनिक स्वच्छता: परियोजना का सार्वजनिक स्वच्छता और स्वच्छता मानकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसने स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दिया।

पुरुष, महिला और दिव्यांगजन के लिए अलग–अलग प्रावधान– नवनिर्मित शौचालय ब्लॉक जिसमें पुरुष, महिला और दिव्यांगजन के लिए व्यवस्था है जो विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करता है और समुदाय को सुविधा प्रदान करता है।

उपयोग की गई धनराशि

इस परियोजना के लिए कुल 20.02 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध ता व्यक्त की गई थी। इस योजना पर कुल 16.16 करोड़ रुपए धन व्यय किया गया।

5. पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कानपुर नगर के गांवों में 50 सोलर आधारित सबमर्सिबल पंप लगाना

उद्देश्य

कानपुर नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को हो रही कठिनाई को देखते हुए एनयूपीपीएल ने जिलाधिकारी कानपुर की अनुशंसा पर कानपुर नगर के 50 गांवों में पम्प रूम के निर्माण और डिस्ट्रिब्यूशन पाइप लाइन बिछाने के साथ सोलर आधारित सबमर्सिबल पम्प लगाने का सीएसआर कार्य शुरू किया है। परियोजना का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा की मदद से ग्रामीणों के लिए पीने का पानी सुनिश्चित करना था। चूंकि कानपुर नगर के कुछ गांवों में पीने के पानी की अनुपलब्धता की गंभीर समस्या थी, इसलिए गर्मियों में यह समस्या और बढ़ जाती है।

लक्ष्य समूह

स्थानीय निवासी, किसान, छात्र, यात्री आदि।

स्थान

कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश के 50 विभिन्न गांव

परिचय

एक ऐसे युग में जहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अत्यधिक महत्व मिला है, एनयूपीपीएल स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए एक अभिनव और सतत दृष्टिकोण पेश करके कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरा। उनकी परियोजना, "पेयजल सुविधा सुनिश्चित करना ", समुदाय के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता का एक साक्ष्य था।

समस्या का विवरण:

भारत के कई अन्य हिस्सों की तरह, कानपुर नगर को अपने गांवों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने में लगातार चुनौती का सामना करना पड़ा। मौजूदा हैंडपंप और पारंपरिक विद्युत पंप अविश्वसनीय थे और अक्सर समुदायों को सुरक्षित पेयजल तक पहुंच के बिना छोड़ दिया जाता था। एनयूपीपीएल ने इस मुद्दे को एक सार्थक बदलाव करने के अवसर के रूप में पहचाना।

समाधान – सौर–आधारित सबमर्सिबल पंप:

एनयूपीपीएल ने कानपुर नगर के विभिन्न गांवों में 50 सौर आधारित सबमर्सिबल पंप स्थापित करके एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। इस अभिनव समाधान ने कई फायदे पेश किए:

सतत और नवीकरणीय ऊर्जा: सौर ऊर्जा ने ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत सुनिश्चित किया, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को समाप्त किया और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया।

प्रभावी लागत: परियोजना ने परिचालन और रखरखाव लागत को काफी कम कर दिया, जिससे ग्रामीणों के लिये स्वच्छ पेयजल अधिक वहनीय हो गया।

विश्वसनीयता: सौर सबमर्सिबल पंपों ने दूरस्थ और ऑफ–ग्रिड स्थानों में भी पानी का एक सुसंगत और भरोसेमंद स्रोत प्रदान किया।

कार्यान्वयन:

एनयूपीपीएल की सीएसआर टीम ने सावधानीपूर्वक योजना बनाई और परियोजना को निष्पादित किया। उन्होंने सबसे अधिक जरूरत वाले गांवों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए, आवश्यक परमिट प्राप्त किए, और सौर–आधारित सबमर्सिबल पंपों की सफल स्थापना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल किया।

प्रमुख उपलब्धियां:

गांवों का चयन: एनयूपीपीएल ने जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों की मदद से कानपुर नगर में स्वच्छ पेयजल तक सीमित पहुंच वाले 50 गांवों की पहचान की।

स्थापना: इंजीनियरों और तकनीशियनों की एक समर्पित टीम ने एनयूपीपीएल प्रभारी इंजीनियर के मार्गदर्शन में प्रत्येक गांव में सौर–आधारित सबमर्सिबल पंप स्थापित किए।

प्रशिक्षण और जागरूकता: एनयूपीपीएल ने पंपों के रखरखाव और संचालन पर ग्रामीणों को शिक्षित करने, स्वामित्व और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए।

प्रभाव:

"पेयजल सुविधा सुनिश्चित" परियोजना ने कानपुर नगर में ग्रामीणों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला:

- **बेहतर स्वास्थ्य:** स्वच्छ पेयजल तक पहुँच से जल से होने वाले रोगों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप समुदायों के लिये समग्र स्वास्थ्य बेहतर हुआ है।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** परिवारों को अब अपनी आय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पानी या चिकित्सा उपचार पर खर्च नहीं करना पड़ता था, जिससे वे शिक्षा और आजीविका में निवेश कर सकते थे।
- **जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि:** परियोजना ने ग्रामीणों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता में योगदान दिया, जिसमें लाभकारी गतिविधियों और विश्राम के लिए अधिक समय उपलब्ध था।

पर्यावरणीय लाभः नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के परियोजना के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई और स्वच्छ वातावरण में योगदान मिला।

संधारणीयताः

समुदायों के लिए एनयूपीपीएल की प्रतिबद्धता परियोजना के स्थापना चरण के साथ समाप्त नहीं हुई। उन्होंने एक समर्पित रखरखाव टीम की स्थापना की और सौर–आधारित सबमर्सिबल पंपों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीणों के साथ जुड़ना जारी रखा।

उपयोग की गई धनराशि

इस परियोजना के लिए कुल 4.68 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। 2023–24 के अंत में, कुल 3.31 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था। यह परियोजना अगले वर्ष भी जारी है।

समाप्तिः

एनयूपीपीएल की सीएसआर परियोजना जीवन को बदलने में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की ताकत को दर्शाती है। सौर ऊर्जा से चलने वाले सबमर्सिबल पंपों के माध्यम से कानपुर नगर के गांवों में स्वच्छ पेयजल लाकर, एनयूपीपीएल ने न केवल समुदाय की प्यास बुझाई है, बल्कि उम्मीद, स्वास्थ्य और समृद्धि को भी बढ़ावा दिया है। यह सफलता की कहानी उस सकारात्मक बदलाव का एक साक्ष्य है जो इन कार्यों से तब समाज में लाया जा सकता है जब वे उन समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं।

6. कानपुर नगर के विभिन्न गांवों में 3 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण

उद्देश्य

परियोजना का उद्देश्य गांवों में बुनियादी ढांचे के सामुदायिक केंद्र विकसित करना है। ये सामुदायिक केंद्र ग्रामीणों के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समारोहों का आयोजन करने और उनके बीच सद्भाव विकसित करने की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

लक्ष्य समूह

गांवों के स्थानीय निवासी

गतिविधि का स्थान

कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील के अमुली, दोहरू, गुजेला गांव

परिचय

एनयूपीपीएल, जो सतत विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध एक प्रमुख कॉर्पोरेट इकाई है, ने घाटमपुर तहसील, कानपुर नगर में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की। एक दूरदर्शी सीएसआर पहल के माध्यम से, एनयूपीपीएल ने विभिन्न गांवों में 3 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करने, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (यूपीपीडब्ल्यूडी) के साथ भागीदारी की। परियोजना, जो वर्तमान में प्रगति पर है, पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुकी है, जिसमें 3 में से 2 सामुदायिक केंद्र लगभग पूरे हो चुके हैं।

चुनौती:

कानपुर नगर का एक ग्रामीण इलाका, घाटमपुर तहसील कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसमें सुलभ सामुदायिक स्थानों की कमी भी शामिल थी, जो सामाजिक संपर्क और सामुदायिक विकास को सीमित करती थी। इन चुनौतियों ने सीएसआर के माध्यम से स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए एनयूपीपीएल के दृढ़ संकल्प को जन्म दिया।

समाधान:

कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में यूपीपीडब्ल्यूडी के साथ एनयूपीपीएल की साझेदारी सफलता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। साथ में, उन्होंने तीन अत्याधुनिक सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करने के लिए एक मिशन शुरू किया जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में काम करेंगे। सामुदायिक भागीदारी और संधारणीयता पर एक मजबूती से ध्यान देने के साथ परियोजना को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया था।

प्रमुख उपलब्धियां:

2 सामुदायिक केंद्रों को पूरा करना: विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, एनयूपीपीएल ने यूपीपीडब्ल्यूडी के सहयोग से दो सामुदायिक केंद्रों को सफलतापूर्वक पूरा किया। ये केंद्र अब अपने–अपने गांवों में आशा और सकारात्मक बदलाव की किरण के रूप में काम करते हैं। अन्य तीसरे सामुदायिक केंद्र में काम पूरे जोरों पर चल रहा है और जून 2024 के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।

- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:** सामुदायिक केंद्र विभिन्न गतिविधियों के लिये केंद्र बिंदु बन गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य शिविरों से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं। इन पहलों ने स्थानीय निवासियों को उनके कौशल, स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाकर सशक्त बनाया है।
- **शिक्षा को बढ़ावा देना:** एनयूपीपीएल ने इन केंद्रों के भीतर कौशल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, चिकित्सा शिविर स्थापित करने, इन ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को शैक्षिक संसाधनों और सीखने के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने की योजना बनाई है।
- **सांस्कृतिक आदान–प्रदान:** सामुदायिक केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोहों और त्योहारों के लिए समुदायों को एक साथ लाया है, एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया है।
- **आर्थिक विकास:** व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रावधान के माध्यम से, परियोजना ने स्थानीय आबादी के लिए आर्थिक अवसरों की सुविधा प्रदान की है, बेरोजगारी और गरीबी को कम किया है।

- **सामुदायिक साक्ष्यः** स्थानीय निवासियों ने एनयूपीपीएल की सीएसआर पहल के लिए अपना आभार व्यक्त किया है, जो उनके जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है। वे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुंच के साथ–साथ समुदाय और गौरव की बढ़ी हुई भावना की बात करते हैं।

आगे की सोचनाः

घाटमपुर तहसील में एनयूपीपीएल की सीएसआर पहल स्थानीय समुदायों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही है। शेष सात सामुदायिक केंद्र निर्माणाधीन हैं, और यह परियोजना आने वाले महीनों में और भी अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए रास्ते पर है। एनयूपीपीएल इन केंद्रों की देख–रेख करने, उनकी दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने और उन समुदायों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिनकी वे सेवा करते हैं।

उपयोग की गई धनराशि

इस गतिविधि के लिए प्रतिबद्ध कुल निधि 1.43 करोड़ रुपये है, जिसमें से एनयूपीपीएल द्वारा मार्च 2024 तक खर्च की गई कुल निधि 0.66 करोड़ रुपये है।

समाप्तिः

कानपुर नगर के घाटमपुर तहसील में एनयूपीपीएल की सीएसआर पहल, जीवन और समुदायों को बदलने में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी की ताकत का साक्ष्य है। यूपीपीडब्ल्यूडी के साथ कार्यनीतिक साझेदारी और सतत विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के माध्यम से, एनयूपीपीएल ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी में उत्कृष्टता का एक उदाहरण स्थापित किया है। 3 में से 2 सामुदायिक केंद्रों का पूरा होना एक यात्रा की शुरुआत है जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश में सकारात्मक बदलाव की स्थायी विरासत छोड़ने का वादा करता है।

7. कानपुर छावनी उत्तर प्रदेश में एनसीसी शिविर प्रशिक्षण क्षेत्र में डाइनिंग शेड सह रसोई हॉल का निर्माण

उद्देश्य

डाइनिंग शेड सह रसोई का प्राथमिक उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को उनके शिविर गतिविधियों के दौरान उनके लिए भोजन तैयार करने और परोसने के लिए एक समर्पित और स्वच्छ स्थान प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों या अन्य शिविर से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के दौरान कैडेटों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिले। यह शिक्षा, प्रशिक्षण और कैडेटों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्र के रूप में भी कार्य करता है।

लक्ष्य समूह

एनसीसी कैडेट, प्रशिक्षक/इंस्ट्रक्टर, सहायक स्टाफ आदि।

गतिविधि का स्थान

कानपुर छावनी, उत्तर प्रदेश में एनसीसी शिविर क्षेत्र

परिचय

कानपुर नगर के जीवंत छावनी क्षेत्र के केंद्र में, एक उल्लेखनीय परियोजना सेवा, समर्पण और समुदाय की भावना को एक साथ लाई है। एनसीसी कैडेटों के डाइनिंग हॉल सह रसोई केंद्र का निर्माण इसमें शामिल सभी लोगों की प्रतिबद्धता और दृढ़ता का साक्ष्य है। यह सफलता की कहानी इस प्रेरक परियोजना की यात्रा का वर्णन करती है, जो एनसीसी कैडेटों और स्थानीय समुदाय के जीवन में लाए गए परिवर्तन को दर्शाती है।

विजनः

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) युवा मन को पोषित करने, अनुशासन पैदा करने और अपने कैडेटों के बीच राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के अपने मिशन के लिए जाना जाता है। कानपुर नगर में, एनसीसी एक चुनौती का सामना कर रहा था। उन्हें कैडेटों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित भोजन और रसोई की सुविधा की आवश्यकता थी। इस तरह की सुविधा की कमी न केवल कैडेटों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी, बल्कि यूनिट के समग्र मनोबल को भी प्रभावित कर रही थी।

यात्राः

एनसीसी कैडेट्स डाइनिंग हॉल सह रसोई केंद्र के निर्माण का दृष्टिकोण एक विनम्र आकांक्षा के रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसने जल्दी ही गति पकड़ ली। एनसीसी अधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों और संबंधित नागरिकों सहित व्यक्तियों

का एक विविध समूह इस विजन को वास्तविकता बनाने के लिए एक साथ आया।

परिश्रमपूर्ण नियोजन और डिजाइन:

एनयूपीपीएल इंजीनियरों की एक अनुभवी टीम ने एक ऐसी सुविधा तैयार करने के लिए सहयोग किया जो न केवल कैडेटों की तत्काल जरूरतों को पूरा करती है बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए संधारणीयता और अनुकूलन क्षमता भी सुनिश्चित करती है। डिजाइन में पर्यावरणीय कारकों, सुरक्षा नियमों और भवन के समग्र अभिरुप पर विचार किया गया।

निर्माण चरण:

निर्माण चरण में स्थानीय मजदूरों और कुशल श्रमिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण पर ध्यान दिया गया था। परियोजना की प्रगति की बारीकी से निगरानी की गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें सुरक्षा मानकों और समयसीमा का पालन हो।

प्रभाव:

एनसीसी कैडेट्स डाइनिंग हॉल सह रसोई केंद्र के पूरा होने से परिवर्तनकारी बदलाव आए हैं:

- **बेहतर पोषण**: एनसीसी कैडेटों के पास अब पौष्टिक भोजन तक पहुंच है, जिससे उनके शारीरिक कल्याण और समग्र परफोर्मेंस को बढ़ावा मिला है।
- **मनोबल में वृद्धि:** एक अच्छी तरह से संरचित सुविधा ने कैडेटों के मनोबल को बढ़ाया है, जिससे उन्हें अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरणा मिली है।
- **सतत भविष्य:** परियोजना के डिजाइन और निर्माण सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि यह आने वाली कैडेटों की पीढ़ियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बना रहे।

उपयोग की गई निधि

इस कार्यकलाप के लिए उपयोग की गई कुल निधि 16.23 लाख है।

समाप्ति:

कानपुर नगर में एनसीसी कैडेट्स डाइनिंग हॉल सह किचन सेंटर का निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आशा, एकता और सामुदायिक कार्रवाई का प्रतीक है। यह अपार क्षमता को प्रदर्शित करता है जब लोग एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक साथ आते हैं, और यह ऐसे साक्ष्य का प्रतीक है कि जहां विजन, समर्पण और कड़ी मेहनत सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिल जाए है तो क्या हासिल नहीं किया जा सकता है।

अनुबंध

एनएलसीआईएल (समेकित) सीएसआर व्यय – 10 वर्ष – 2023–24 तक (अनंतिम)

सं.	सीएसआर गतिविधियां	2023-24 (अनं)	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	चिकित्सा–स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	10.09	14.14	11.91	6.57	22.70	6.44	5.57	6.94	43.81	6.73
2	पीने के पानी की सुविधा	25.41	8.18	0.56	1.51	1.35	1.06	1.55	0.00	0.13	0.90
3	शिक्षा और छात्रवृत्ति	12.01	25.14	14.70	14.70	6.71	15.46	7.95	10.48	24.15	15.47
4	लिंक रोड का निर्माण	0.88	2.06	0.00	0.72	1.86	1.28	4.10	2.39	9.85	11.78
5	खेलों को बढ़ावा	0.48	0.57	0.28	0.05	0.42	0.40	0.41	0.33	0.00	0.04
6	सामुदायिक विकास केंद्र	3.05	0.07	0.69	0.45	0.85	0.13	0.20	0.11	0.17	0.24
7	वनीकरण और पर्यावरण स्थिरता	0.14	0.00	0.65	0.16	0.10	1.63	2.17	0.14	0.12	0.04
8	स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाएं	0.00	0.00	18.02	2.31	11.70	1.86	0.94	1.44	0.00	0.00
9	विरासत, कला और संस्कृति, स्कूल, पुस्तकालय और छात्रावास का निर्माण	1.64	0.16	0.40	0.06	2.25	1.23	1.72	1.35	0.62	0.23
10	व्यावसायिक कौशल का केंद्र विकास	1.20	0.00	0.01	0.82	1.42	3.01	1.76	0.44	0.21	0.09
11	सिंचाई सुविधाएं	1.36	0.00	0.00	5.15	7.16	10.15	11.06	8.11	2.87	10.97
12	सौर और गैर–पारंपरिक ऊर्जा सहित इलेक्ट्रिसिटी	0.00	0.00	0.00	0.75	0.39	1.69	0.85	0.00	0.00	0.00
13	प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	0.00	0.14	0.01	0.00	0.00	1.16	0.00	0.06	0.00	1.01
14	वृद्धाश्रम को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	1.84	0.42	0.00	0.00
15	सशस्त्र बलों में योगदान	0.08	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
16	अन्य	3.42	2.47	1.22	19.55	32.88	7.47	4.85	5.70	0.71	0.25
कुल व्यय		**59.77**	**52.99**	**48.46**	**52.79**	**89.78**	**53.15**	**45.03**	**37.91**	**82.64**	**47.74**